भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **594**

दिनांक 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सेलुलर फोन का आयात और निर्यात

594. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य सहित देश में विगत तीन वर्षों के दौरान सेलुलर फोन के आयात और निर्यात की कुल संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक सामान का विनिर्माण उद्योग शुरू करने के लिए किसी नए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) संचालनरत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग की मदों का कुल हिस्सेदारी प्रतिशत कितना है; और

(घ) भारत द्वारा अन्य देशों से इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद की निर्भरता का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

क. तमिलनाडु राज्य सहित देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान मोबाइल फोन के कुल आयात और निर्यात की कुल संख्या निम्नवत है:

मोबाइल फोन का निर्यात

(आंकड़े लाख में)

एचएस कोड	वस्तु विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
85171110	पुश बटन वाला	0.03	0.63	0.25
85171190	अन्य	0.42	0.65	0.42
85171219	मोबाइल फोन, पुश बटन वाला	0.21	0.00	0.00
85171290	अन्य	0.20	0.00	0.00
85171300	स्मार्टफोन	70.84	151.53	226.31
85171400	सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस के लिए अन्य टेलीफोन	0.11	0.00	0.00
85171810	पुश बटन वाला	0.15	0.24	0.40
85171890	अन्य	2.27	0.40	1.35
सकल योग		**74.23**	**153.45**	**228.73**

मोबाईल फोन का आयात

(आंकड़े लाख में)

एचएस कोड	वस्तु विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
85171110	पुश बटन वाला	9.54	8.31	5.56
85171190	अन्य	5.75	1.13	1.25
85171290	अन्य	0.31	0.00	0.00
85171300	स्मार्टफोन	23.39	15.38	8.88
85171400	सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस के लिए अन्य टेलीफोन	10.46	12.97	6.33
85171810	पुश बटन वाला	4.89	3.17	4.74
85171890	अन्य	4.32	5.44	3.36
सकल योग		**58.66**	**46.40**	**30.12**

(ख) और (ग) भारत सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना, 'मेक इन इंडिया' के तहत सरकार का निरंतर ध्यान, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित विनिर्माण मिशन और निर्यात संवर्धन मिशन जैसी योजनाएं अखिल भारतीय स्तर की पहल हैं, जो किसी विशेष राज्य तक सीमित नहीं हैं। इसके अलावा, उन कंपनियों (जिन्हें उचित प्रक्रिया के बाद चुना जाता है) को लाभ दिया जाता है, जो अपनी इकाइयों का स्थान तय करती हैं।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मूल रूप से वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर आधारित है, जहां उत्पादन कई देशों और चरणों में फैला हुआ है। हालांकि भारत ने परिसज्जित माल में मजबूत क्षमताएं विकसित की हैं। मुख्य रूप से मोबाइल फोन और कई उप-असेंबलीज के विनिर्माण में यह कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स और घटकों के लिए आयात पर निर्भर है।

इस समस्या के संरचनात्मक समाधान हेतु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) शुरू की है। यह योजना डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, पीसीबीए, मैकेनिक्स, कनेक्टर और अन्य महत्वपूर्ण इनपुटस सहित प्रमुख उप-असेंबलीज और घटकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। समय के साथ, ईसीएमएस से घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि होने, आयात पर निर्भरता में कमी होने और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति के मजबूत होने की प्रत्याक्षा है।

*****